

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1944 (श0) (सं0 पटना 249) पटना, शुक्रवार, 29 अप्रील 2022

विधि विभाग

अधिसूचना 29 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–22/2021–4062/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 28 अप्रैल, 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 11, 2022]

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 20, 2013) में संशोधन करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावना:— राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 अधिनियमित है। इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 में निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में वर्णित शर्तों को अनुपालित करने की समय—सीमा निर्धारित है। राज्यहित में इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के परंतुक में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

इसलिए, भारत—गणराज्य के बहतरवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. संक्षिप्त नाम. विस्तार एवं प्रारम्भ ।-
 - (1) यह अधिनियम बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह दिनांक 01.04.2021 से प्रवृत होगा।
- 2. **बिहार अधिनियम 20, 2013 की धारा 5 का संशोधन** |— बिहार अधिनियम 20, 2013 की धारा 5 की उप धारा (2) के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"परंतु प्रायोजक निकाय द्वारा आशय पत्र में वर्णित समयाविध में प्रयास करने के बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन उचित कारणों से समर्पित किये जाने में असफल रहने की स्थिति में राज्य सरकार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की अविध को यथोचित अविध के लिए विस्तारित कर सकेगी।"

> उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।

29 अप्रील 2022

सं० एल०जी०-01-22/2021-4063/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 अप्रील, 2022 को अनुमत बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 11, 2022) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 11, 2022] THE BIHAR PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2021

AN ACT

To amend the The Bihar Private Universities Act 2013 (Bihar Act 20, 2013)

The Bihar Private Universities Act, 2013 has been enacted for establishment of Private Universities in the state of Bihar with the aim to provide access to quality higher education. Sub section (2) of section 5 of this Act deals with the provisions of time period fixed for the submission of compliance report against the letter of intent issued for establishment of a Private University. In the interest of the state, it is expedient to make amendments in the proviso of sub section (2) of section 5 of the Bihar State Private University Act, 2013.

Therefore, be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy second year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.—
 - (1) This Act may be called the Bihar Private Universities (Amendment) Act, 2021.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force from 01.04.2021.
- **2.** Amendment of Section 5 of Bihar Act 20, 2013.—The Proviso of sub section (2) of section 5 of The Bihar Private Universities Act, 2013 (Bihar Act 20, 2013) shall be substituted by the following:-

"Provided that where in spite of making efforts, the sponsoring body has failed to submit compliance report during the time period mentioned in the letter of intent for valid reasons the state government may extend the time period for submission of compliance report for such period as deemed fit."

Umesh Kumar Sharma

Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 249-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in